राष्ट्रपति के 2025 के अभिभाषण के मुख्य अंश

भारत की राष्ट्रपति सुश्री द्रौपदी मुर्मू ने 31 जनवरी, 2025 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में सरकार की प्रमुख नीतिगत उपलब्धियों और उद्देश्यों को स्पष्ट किया। संबोधन के मुख्य अंश इस प्रकार हैं:

गवर्नेंस

- सरकार ने 1,500 से अधिक अप्रचलित कानूनों को निरस्त कर दिया है। 40,000 से अधिक रेगुलेशंस को सरल या कम किया गया है और 3,500 प्रावधानों को अपराधमुक्त किया गया है।
- पिछले दो वर्षों में सरकार ने 10 लाख स्थायी सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं।
- आठवें वेतन आयोग का गठन हो चुका है। इससे आने वाले वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में काफी वृद्धि होगी।
- एकीकृत पेंशन योजना के तहत लाखों कर्मचारियों को 50% सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी।
- कर संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। फेसलेस मूल्यांकन से पारदर्शिता बढ़ रही है और कर विवाद कम हो रहे हैं।

कृषि

- पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हाल के महीनों में करोड़ों किसानों को 41,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं।
- खरीफ और रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि हुई है। पिछले एक दशक में चावल, गेहूं, दालें, तिलहन और मोटे अनाज की खरीद तीन गुना हो गई है।
- 2023-24 में भारत ने 332 मिलियन टन खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन हासिल किया है। भारत अब दूध, दालों और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है।
- खेती के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना का विस्तार किया गया है।
- तिलहन का उत्पादन बढ़ाने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए राष्ट्रीय तिलहन मिशन को मंजूरी दी गई है।

उद्योग एवं वाणिज्य

- मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। भारत में अब 1.5 लाख से अधिक स्टार्ट-अप्स हैं।
- एमएसएमई और ई-कॉमर्स निर्यात केंद्रों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
- देश भर के शहरों के पास 12 औद्योगिक नोड स्थापित करने और 100 औद्योगिक पार्क बनाने के लिए 28,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
- मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने युवाओं के लिए रोजगार के असंख्य अवसर पैदा किए हैं।
- दुनिया के 50% से अधिक रियल-टाइम डिजिटल लेनदेन अब भारत में होते हैं।

शिक्षा एवं खेल

- मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की गई है।
- एक करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर दिए जाएंगे।
- शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु 50,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन बनाया गया है।
- अनुसंधान में सरलता के लिए वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की गई है। यह अंतरराष्ट्रीय शोध सामग्री तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करती है।
- खेलो इंडिया योजना, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स), राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विश्व

वैशाली धारीवाल
vaishali@prsindia.org

31 जनवरी, 2025

स्तर के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को बनाने में योगदान दे रहे हैं।

- युवाओं के लिए कौशल बढ़ाने और नए अवसर पैदा करने के लिए सरकार ने दो लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है।

स्वास्थ्य

- मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में सुधार हुआ है। टीबी के मामले कम हुए हैं।
- आयुष्मान भारत के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को सालाना पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा।
- जन औषधि केंद्र 80% रियायती दरों पर दवाएं प्रदान करते हैं जिससे 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है।
- देश भर में 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं जिससे नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकें।
- कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या और उपचार की उच्च लागत के कारण कैंसर की कई दवाओं को सीमा शुल्क से छूट दी गई है।
- अगले पांच वर्षों में मेडिकल कॉलेजों में 75,000 नई सीटें बनाई जाएंगी।

सामाजिक न्याय

- शौचालयों, जल कनेक्शन और राशन के प्रावधानों से 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निजात मिली है।
- समाज के पिछड़े वर्गों और सैनिटेशन वर्कर्स को आसान ऋण प्रदान करने के लिए पीएम-सूरज योजना का विस्तार किया गया है।
- दिव्यांग व्यक्तियों तक सरकारी योजनाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक करोड़ से अधिक दिव्यांग पहचान पत्र जारी किए गए हैं।
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य, कृषि, पोषण और शिक्षा में सुधार करेगा।
- आदिवासी समुदायों के पांच करोड़ लोगों के उत्थान के लिए 80,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ धरती आबा आदिवासी ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया है।
- 470 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में लगभग 1.25 लाख आदिवासी बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
- सिकल सेल एनीमिया के लिए लगभग पांच करोड़ आदिवासी व्यक्तियों की जांच की गई है।

महिला सशक्तीकरण

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को जोड़कर 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाया जा रहा है। उन्हें बैंक लिंकेज के माध्यम से नौ लाख करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त हुए हैं।
- कृषि सखियां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही हैं और पशु सखियां हमारे पशुधन संसाधनों को मजबूत कर रही हैं। लगभग एक करोड़ लखपति दीदियां उद्यमी के रूप में अपने परिवार का भरण-पोषण कर रही हैं।

ग्रामीण एवं शहरी विकास

- तीन करोड़ और परिवारों को घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार किया गया है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV से 25,000 बस्तियों को सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी।
- स्वामित्व योजना के तहत दो करोड़ संपत्ति कार्ड जारी किए गए हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर एवं परिवहन

- पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने परियोजना पूर्णता की गति को तेज किया है।
- देश की एयरलाइन कंपनियों ने 1,700 से अधिक नए विमानों का ऑर्डर दिया है। सरकार इस बेड़े को संचालित करने के लिए हवाई अड्डों का विस्तार कर रही है। पिछले एक दशक में देश में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हो गई है।
- सरकार ने स्वच्छ शहरी परिवहन प्रदान करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से देश में 52,000 इलेक्ट्रिक बसें तैनात करने की योजना बनाई है।
- भारत का मेट्रो नेटवर्क 1,000 किलोमीटर से

अधिक का है और यह दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है।

जल, पर्यावरण एवं ऊर्जा

- नदी जोड़ो परियोजनाएं, जो चालू हैं, वे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई और पेयजल की जरूरतों को पूरा करेंगी।
- सरकार ने 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं।
- पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 75,000 करोड़ रुपए की लागत से रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं।
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में आठ लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा और छह लाख से अधिक नौकरियां पैदा होंगी।
- सरकार ने पुराने वाहनों का वैज्ञानिक निपटान सुनिश्चित करने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति पेश की है।

विज्ञान एवं तकनीक

- अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड शुरू किया गया है।
- क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इसकी रैंक 76 से बढ़कर 39 हो गई है।
- विज्ञान धारा योजना के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है।
- बायो-मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बायोई3 नीति शुरू की गई है। जैव-अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का लक्ष्य भारत को फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी देशों में स्थान दिलाना है।
- राष्ट्रीय एआई मिशन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के योगदान को बढ़ाया है।

रक्षा एवं गृह मामले

- डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना और डिफेंस स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देकर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत किया जा रहा है।
- सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कें और सुरंगें रक्षा क्षमताओं को बढ़ा रही हैं।
- वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर 38 हो गई है।
- पूर्वी राज्यों के लिए एक व्यापक विकास योजना बनाई जा रही है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

स्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार की गई है। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी की मूल रिपोर्ट से इसकी पुष्टि की जा सकती है।